इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 03 अक्तूबर 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विनियामकों के कथन ----------4
विदेशी मुद्रा----------5
पूंजी बाज़ार----------6
सूक्ष्मवित्त ----------6
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------6
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------7
संस्थान समाचार----------7
महत्वपूर्ण दरें / अनुपात ----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 8
शब्दावली ----------8
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्त्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्त्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्य-तिमाही नीतिगत समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक की मध्य-तिमाही नीतिगत समीक्षा -सितम्बर 2010

वैश्विक परिदृश्य

27 जुलाई 2010 को संपन्न भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति की पहली तिमाही की समीक्षा में वैश्विक परिदृश्य पर चिंता व्यक्त की गई थी। आर्थिक गतिविधि के संकेतकों से इस बात का निरंतर पता लगता है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पुनरुत्थान धीमा पड़ रहा है तथा वर्ष 2010 के द्वितीयार्ध में प्रथमार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी वृद्धि परिलक्षित होगी, यद्यपि जुलाई के अंत से अपेक्षाओं में सामान्य रूप से संशोधन नहीं किया गया है।

घरेलू परिदृश्य

स्थूल-आर्थिक प्रबन्धन में मुद्रास्फीति प्रबल चिंता बनी हुई है। मुद्रास्फीति की दरें एक निश्चित मुकाम पर पहुंच गई हैं, किन्तु उनके कुछेक माह तक अस्वीकार्य रूप से एक उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है। इस प्रकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए तथा स्फीतिकारक प्रत्याशाओं को रोकने के लिए निरंतर नीतिगत अनुक्रिया की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

मुद्रास्फीति से सम्बन्धित चिंता का एक अन्य पहलू है वास्तविक ब्याज दरों पर होने वाले उसके निहितार्थ। पिछली तीन तिमाहियों में की गई नीतिगत कार्रवाइयां आंशिक रूप से नकारात्मक वास्तविक ब्याज दरों के प्रचलन को समाप्त किए जाने की आवश्यकता द्वारा अभिप्रेरित रही हैं। नकारात्मक वास्तविक दरों से बैंकों की जमा-वृद्धि में कमी आ जाती है, क्योंकि बचतकर्ता अन्यत्र अपेक्षाकृत अधिक प्रतिलाभ की ताक में रहते हैं। यदि बैंक ऋण वृद्धि में रुकावट न बनने वाले हों, तो वास्तविक दरों का बैक जमाराशियां बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होना आवश्यक हो जाता है। हाल के महीनों में मौद्रिक नीति के उद्देश्यों से चलनिधि

एक महत्वपूर्ण कारक रही है। विदेशी मोर्चे पर, मंद वैश्विक अर्थव्यवस्था निर्यात वृद्धि को अवरुद्ध कर देती है, जबकि सुदृढ़ घरेलू पुनरुत्थान ने आयात की मांग बढ़ा दी है। फलत: व्यापार घाटा और उसके साथ ही चालू खाते का घाटा बढ़ रहे हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में आई दृश्यमान स्थिरता से वैश्विक स्तर पर निवेशक मनोभाव में वृद्धि हुई लगती है, जिसके परिणामस्वरूप उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी अन्तर्वाहों में स्थिर वृद्धि हुई है। इस प्रवृत्ति के जारी रहने पर विदेशी मोर्चे पर जोखिमों में, निर्यात के मंद बने रहने के बावजूद कमी आएगी।

प्रमुख विशेषताएं

मौद्रिक उपाय

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (repo) दर में तात्कालिक प्रभाव से 25 आधार अंकों (bps) की वृद्धि, जो 5.75% के बजाय 6.0% हो गई।

चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद (reverse repo) दर में तात्कालिक प्रभाव से 50 आधार अंकों (bps) की वृद्धि, जो 4.50% के बजाय 5.0% हो गई।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 6% की दर पर अपरिवर्तित।

बैंकों द्वारा न्यूनतम दरें, आधार दरें बढ़ाए जाने की आशा।

मुख्य घटनाएं

एअरटेल सेल फोनों पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगा

एक अत्यधिक प्रगतिशील मुहिम के तहत भारत के सबसे बड़े दूरसंचार प्रचालक - भारती एअरटेल को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उस सफरी थैले, जो मोबाइल प्रयोक्ताओं को अस्थिर नकदी का उपयोग किए बिना उत्पादों/ सेवाओं को खरीदने की सुविधा प्रदान करता है, का उपयोग करने का पहला लाइसेंस प्रदान किए जाने के बाद उक्त प्रचालक मोबाइल फोनों पर वित्तीय सेवाएं आरंभ करने हेतु तत्पर है।

राष्ट्रीय आवास बैंक संपत्ति से सम्बन्धित सूचना के लिए ई-रजिस्ट्री की स्थापना करेगा

आवासीय वित्त कम्पनियों का विनियामक निकाय, राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) भारत के आवासीय ऋण बाज़ार को सुदृढ़ करने हेतु कमर कस रहा है। अन्य 10 शीर्ष बैंकों के साथ मिल कर राष्ट्रीय आवास बैंक

बंधक के अधीन संपत्ति से सम्बन्धित सूचना के लिए एक विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) के माध्यम से एक समान इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री प्रणाली की स्थापना करने की दिशा में काम कर रहा है। उसने संपत्ति की कीमतों में एकरूपता लाने के लिए मूल्यांकन मानकों पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है।

डेबिट कार्डों की शुरूआत करने हेतु डाक विभाग को भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति मिली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने डाक विभाग (DoP) को अपने ऐसे पूर्व-प्रदत्त डेबिट कार्डों की शुरूआत करने की अनुमति प्रदान कर दी है, जो ग्राहकों को देश भर के मुख्य खुदरा बिक्री केन्द्रों से उत्पाद खरीदने की सुविधा प्रदान करेंगे। डाक विभाग के पूर्व-प्रदत्त डेबिट कार्डों का न्यूनतम मूल्य 1,000 रुपये और अधिकतम मूल्य 50,000 रुपये होगा। आगे चलकर ये कार्ड अपेक्षित मूल्य में उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राहक इस कार्ड का उपयोग करते हुए एटीएमों से धनराशि आहरित करने में भी समर्थ होंगे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अधिकारियों, लिपिकों की भर्ती के लिए परीक्षा शीघ्र ही

सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में अधिकारियों, लिपिकों की भर्ती करने हेतु एक साझी भर्ती परीक्षा संचालित करने का निर्णय लिया है। यह परीक्षा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन) द्वारा संचालित की जाएगी। साझी परीक्षा का यह सुझाव बैंक ऑफ बड़ौदा BoB) के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉ. ए.के. खण्डेलवाल की अध्यक्षता में गठित एक समिति से प्राप्त हुआ था।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी बैंकों के सहायक कम्पनियों के माध्यम से प्रवेश के पक्ष में

भारत में प्रवेश के इंच्छुक विदेशी बैंकों को शीघ्र ही अनिवार्य रूप से पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी (WOS) वाला मार्ग अपनाना पड़ सकता है। भारत में विदेशी बैंकों के परिचालनों पर बेहतर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक इस आशय के एक नीतिगत परिवर्तन पर विचार कर रहा है। वर्तमान में विदेशी बैंक या तो केवल शाखाओं वाले मार्ग का उपयोग कर सकते हैं या फिर पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी वाला विकल्प अपना सकते हैं, किन्तु व्यावहारिक तौर पर बाद वाला मार्ग कभी नहीं अपनाया जाता। अधिकांश विदेशी बैंक पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी वाले उस मार्ग को अपनाना पसंद नहीं कर सकते, जिसमें उन्हें उचित अनुपात में लाभ के बिना ही प्रवेश के लिए अधिक पूंजी लगानी होगी। जब तक उन्हें राष्ट्रीय जैसा दर्जा नहीं प्रदान किया जाता, इस बात की परवाह किए बिना कि केवल शाखाओं वालामार्ग अपनाया गया है या फिर पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनी वाला, भारत में शाखा विस्तार परिसीमित ही रहेगा। भारतीय शेयर बाज़ारों में संभाव्य सूचीबद्धता, जो घरेलू निगमन के मामले में आवश्यक हो सकती है, भी उनकी चिंता का एक मुद्दा बन सकती है।

बचत खातों की दरों का अविनियमन भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन - सुश्री थोरात

भारतीय रिज़र्व बैंक बचत खातों से सम्बन्धित ब्याज दरों के अविनियमन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और वह शीघ्र ही इसे कार्यान्वित करने का प्रयास कर सकता है यह कहना है भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर सुश्री उषा थोरात का। सुश्री थोरात इसके आगे यह भी कहती हैं कि "लागत वसूली में पारदर्शिता अविनियमन को सुगम बना सकती है। इसे सभी स्थलों पर गैर-भेदभावपरक बनाना भी आवश्यक होगा।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शेयरों पर बैंक वित्त के नियमों को कठोर बनाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रवर्तकों को शेयरों पर ऋण प्रदान करने वाले बैंकों के लिए मानदंडों को कठोर बना दिया है। उसने इक्विटी पूंजी के रूप में प्रवर्तकों के अंशदान के वित्तीयन हेतु अग्रिम प्रदान करने वाले बैंकों के विरुद्ध विद्यमान प्रतिबंध को गैर-प्रतियोगी शुल्क आदि के भुगतान जैसे अभिग्रहण से सम्बन्धित गतिविधियों का वित्तीयन करने वाले बैंक तक विस्तारित कर दिया है। इस प्रकार का प्रतिबंध ऐसी गतिविधियों के लिए बैंक वित्त की व्यवस्था करने वाली भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं / सहायक कम्पनियों पर भी लागू होगा।

लाभार्जन के लिए फर्मों को वित्तीय समावेशन में भूमिका मिली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब विशाल एवं व्यापक फैलाव वाले खुदरा बिक्री केन्द्र रखने वाली लाभार्जन के लिए कम्पनियों को कारबार संपर्की (BC) के रूप में काम करने की अनुमति प्रदान कर दी है। उक्त मुहिम से वित्तीय समावेशन को गहनता एवं व्यापकता, दोनों ही प्राप्त होगी। भारतीय रिज़र्व बैंक यह महसूस करता है कि इस प्रकार की कम्पनियां वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के अलावा, कारबार संपर्कियों के नेटवर्क के लिए आवश्यक अपेक्षाकृत अधिक संसाधन, संगठनात्मक शक्ति तथा वित्तीय सहारा प्रदान करती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार व्यक्तियों की अपेक्षा किसी कारपोरेट के कारबार संपर्की के रूप में काफी लम्बी आवधि तक बने रहने की संभावना होती है, इस प्रकार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती है। उन्होंने कुशल नकदी प्रबन्धन तथा खुदरा बिक्री केन्द्र निगरानी प्रणालियां विकसित कर रखी हैं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

आईडीबीआई ने नये बेंचमार्क नियत किए, खातों के लिए किसी प्रकार का जमा शेष जरूरी नहीं

अपने चालू एवं बचत खाता (CASA) जमाराशियों के अंश को बढ़ाने के उद्देश्य से आईडीबीआई (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) ने इन खातों में न्यूनतम जमा शेष की संकल्पना को समाप्त कर दिया है तथा नकारे गे चेकों को छोड़कर अधिकांश सेवा प्रभारों को माफ कर दिया है। आईडीबीआई के अध्यक्ष एवं

प्रबन्ध निदेशक श्री आर. एम. मल्ला का कहना है कि इस मुहिम का लक्ष्य अल्प लागत वाली (बचत और चालू) जमाराशियों, जो 14% के स्तर पर हैं, को बढ़ाना है, क्योंकि आईडीबीआई के तुलनपत्र का एक बड़ा हिस्सा पूर्ववर्ती आईडीबीआई से उद्भूत होता था, जो व्यापक तौर पर थोक निधियों पर निर्भर करता था।

एनपीसी ने अंतर बैंक निधियों का ई-अंतरण आरंभ किया

भारतीय रिज़र्व का अनुमोदन प्राप्त हो जाने के बाद सरकार द्वारा स्वाधिकृत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPC) ने मोबाइल उपकरणों के उपयोग के माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक को निधियों का तात्क्षणिक अंतरण सुगम बनाने के लिए निधियों के अंतर बैंक अंतरण पर प्रायोगिक कार्यक्रम आरंभ कर दिया है।

सितम्बर माह में ऋण की मांग में तीव्र वृद्धि परिलक्षित

लगभग दो माह तक मंद वृद्धि से गुजरने के बाद ऋणों की मांग में सितम्बर माह के पहले 10 दिनों में तेजी से वृद्धि दर्ज हुई। व्यवसाय जगत और व्यक्तियों को दिए गए ऋणों में 27,699 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वे 3,331,809,78 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गए। 2 जुलाई, 2010 के बाद से यह पखवाड़े की सर्वोच्च वृद्धि थी, जिसके दौरान दूरसंचार कम्पनियों को उनके 3 ाी लाइसेंस शुल्कों का भुगतान करने में समर्थ बनाने के लिए बैंकों ने 90,492 करोड़ रुपये का रिकार्ड उधार दिया था।

बासेल III मानदंडों को पूरा करने हेतु बैंकों को 6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी की दरकार : आईसीआरए

साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी भारतीय निवेश सूचना और साख श्रेणी निर्धारण एजेन्सी (ICRA) का दावा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता स्तरों पर प्रस्तावित बासेल III दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए आगामी नौ वर्षों में विदेशी पूंजी में 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की आवश्यकता होगी। उक्त एजेन्सी ने चेतावनी दी है कि मुख्य पूंजी के अपेक्षाकृत अधिक स्तर से बैंकों की लाभ उठाने की क्षमता में कमी आने के अलावा उनका इक्विटी पर प्रतिलाभ कम हो सकता है। तथापि, अब भी भारतीय बैंकों के लिए उनके कुछेक अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में यह संक्रमण आसान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि भारत में पूंजी पर्याप्तता से सम्बन्धित विनियामक मानदंड पहले सी अधिक कठोर हैं। इसके अलावा, अधिकांश भारतीय बैंकों ने परंपरागत रूप से अपनी मुख्य एवं समग्र पूंजी न्यूनतम विनियामक स्तर से काफी अधिक स्तर पर बनाए रखा है।

अधिक दरें प्रभावी होती हैं : बैंक जमाराशियों में 14.4% की बढ़ोत्तरी

अधिक जमा दरों को अंतत: ग्राहकों को रिझाने में सफलता मिल ही गई। 27 अगस्त को समाप्त पखवाड़े के दौरान बैंक जमाराशियों में पिछले पखवाड़े में आई 8,000 करोड़ रुपये की गिरावट की तुलना में 38, 658

करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जमाराशियों में वर्षानुवर्ष आधार पर 14.44 % की वृद्धि हुई। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनकी पहली तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा में बैंको से उनके जमा संग्रहण को बढ़ाने के लिए कहे जाने के बाद उन्होंने दरें बढ़ाना आरंभ कर दिया था।

बासेल III मानदंड पूरा करने हेतु बैंकों द्वारा विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा बढ़ाने की आपाधापी

देश के निजी क्षेत्र के उधारकर्ता बासेल III मानदंडों के परिफ्रेक्ष्य में अपनी शेयरधारिता में विदेशी संस्थागत निवेश (FII) की सीमा बढ़ाए जाने के लिए आपाधापी कर रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि विदेशी संस्थागत निवेश सीमा भावी इक्विटी अथवा अर्ध इक्विटी अपेक्षाओं के समक्ष बीमित करेगी। बासेल III में बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपनी जोखिम वाली आस्तियों के कुल 7% जितनी शीर्ष गुणवत्ता वाली पूंजी धारित करें, जो बैंकों को भविष्य में पूंजी जुटाने के लिए आपाधापी करने पर विवश कर सकती है।

बैंकों ने जमा प्रमाणपत्रों के माध्यम से संख्याएं बढ़ाईं

वर्तमान वित्तीय वर्ष में जमाराशियों में हुई कमजोर वृद्धि ने बैंकों को जमा प्रमाणपत्र (CDs) बाज़ार का भारी पैमाने पर दोहन करने हेतु विवश कर दिया है। हाल के दिनों में जमा प्रमाणपत्र निर्गमन लगभग 9000 करोड़ रुपये रहा है, - जो 21 सितम्बर, 2010 के दिन के स्तर से दो गुने से भी अधिक है। जहां काफी अधिक निधियां अन्य अल्पावधिक लिखतों के माध्यम से जुटाई गईं, वहीं बैंकों द्वारा 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम तीन माह के जमा प्रमाणपत्र जारी करते हुए जुटाई गई थी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 7.04% पर 1, 325 करोड़ रुपये जुटाए। यूकों बैंक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) ने भी अल्पावधिक निधियां जुटाईं। लगभग 3,165 करोड़ रुपये मूल्य के अल्पावधिक मुद्रा बाज़ार लिखत अभिनियोजित किए गए। इसके पूर्व 3, 500 करोड़ रुपये से थोड़े कम मूल्य वाले लिखत अभिनियोजित किए गए थे।

अधिक मूल्य वाले विदेशी बॉण्डों ने खज़ाना आय बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई

उधार लेने के स्तर में कमी लाने तथा प्रतिफल घटाने के लिए सरकारी बॉण्डों में अपेक्षाकृत अधिक विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई मुहिम के बाद बैंकों द्वारा खजाना अर्जनों को बढ़ावा प्राप्त होने की आशा है। नियत आय वाली प्रतिभूतियों और जिंसों के क्रय-विक्रय के प्रमुख श्री आशीष वैद्य का कहना है कि "मुझे 10 वर्षीय बेंचमार्क पर प्रतिफल के घटकर 7.85% पर आने की आशा है।" सरकारी बॉण्डों में विशेषत: केन्द्र के इस वर्ष की दूसरी छमाही में उसकी उधारियों में 10, 000 करोड़ रुपये की कमी लाई जाने का निर्णय लिए जाने के बाद वापसी की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है। सरकार ने सरकारी बॉण्डों में विदेशी निवेश की सीमा को भी दो गुना बढ़ा कर 10 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया है तथा दीर्घावधिक कारपोरेट बॉण्डों मे विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा को 15 बिलियन अमरीकी डालर

से बढ़ा कर 20 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया है। नयी उधार (लेने की) योजना के अनुसार केन्द्र इस वित्तीय वर्ष में अक्तूबर और मार्च के बीच वाली अवधि में केवल 4.47 लाख करोड़ रुपये जुटाएगा।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों एवं ऋणों से सम्बन्धित तिमाही सांख्यिकी -मार्च, 2010

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सेवा प्राप्त बैंक सेवा संपन्न केन्द्रों की संख्या 34, 801 थी। इन केन्द्रों में से 27, 946 एकल कार्यालय वाले केन्द्र थे तथा 65 केन्द्रों में 100 या उससे अधिक कार्यालय थे। जमाराशियों के आकार के अनुसार समूहित शीर्ष सौ केन्द्रों की कुल जमाराशियों में हिस्सेदारी 69.4 प्रतिशत रही तथा बैंक ऋणों के अनुसार समूहित शीर्ष सौ केन्द्रों की कुल बैंक ऋणों में हिस्सेदारी 78.0 प्रतिशत थी। शीर्ष सौ केन्द्रों की समग्र जमाराशियों में एक वर्ष पहले मार्च 2009 में दर्ज 21.0 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2010 में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। शीर्ष सौ केन्द्रों के सकल बैंक ऋणों की वृद्धि दर मार्च 2010 में 16.3 प्रतिशत थी, जो मार्च 2009 में दर्ज 20.5 प्रतिशत की तुलना में पर्याप्त रूप से कम थी। समग्र जमाराशियों की दृष्टि से शीर्ष 200 केन्द्रों में 32.1 प्रतिशत रिपोर्टकर्ता कार्यालयों तथा समग्र जमाराशियों के 74.4 प्रतिशत का समावेश था। सकल बैंक ऋणों की दृष्टि से शीर्ष 200 केन्द्रों का हिस्सा सकल बैंक ऋण का 81.5 प्रतिशत तथा रिपोर्टकर्ता कार्यालयों का 31,7 प्रतिशत था।

चलनिधि में आपूर्ति सहज किन्तु कसावट आसन्न

अर्थशास्त्रियों और बैंकरों ने कहा है कि बैंकों के पास उपलब्ध चलनिधि में हाल में हुई बढ़ोत्तरी के भारतीय रिज़र्व बैंक के इस मुद्दे को उसकी चिंता वाली सूची से निकाल देने के प्रति आश्वस्त कर पाने की संभावना नहीं है। येस बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री सुश्री सुभदा राव का कहना है कि "चलनिधि सरकारी राजस्व को सरकार द्वारा खर्च किए जाने के रूप में आ रही है।" उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सरकार का नकदी शेष कम (लगभग 9 सप्ताह पहले के 265 बिलियन रुपये के आसपास की तुलना में 20 अगस्त को 1.1 बिलियन रुपये) था। कसावट मई के अंत में सरकार को तीसरी पीढ़ी के मोबाइलो तथा व्यापकबैंड बेतार पहुंच स्पेक्ट्रम के शुल्क के रूप में 1.1 ट्रिलियन रुपये, अपेक्षित रकम का तीन गुना, प्राप्त होने के बाद आई। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी थी कि जब तक स्पेक्ट्रम की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व सरकार द्वारा खर्च नहीं कर दिया जाता, चलनिधि की स्थिति कठिन बनी रहेगी।वित्त मंत्री को 683 बिलियन रुपये की अतिरिक्त रकम खर्च करने हेतु संसद का अनुमोदन अगस्त में प्राप्त हुआ। यह इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग का पहला समूह था।

वर्ष 2009-10 में आस्तियों पर बैंकों के प्रतिलाभ में कमी

31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष में वाणिज्यिक बैंकों उनके आस्तियों पर प्रतिलाभ (RoA) में कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि निधीयन लागतों में कमी को ग्राहकों से वसूल की जाने वाली ब्याज दरों मे

गिरावट को समायोजित करने में असमर्थ थी। आस्तियों पर प्रतिलाभ, जिसे कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लाभ कहा जाता है वर्ष 2008-09 के 1.13% से घट कर वर्ष 2009-10 में 1.05% रह गया। सभी बैंकों के

मामले में निधि लागत पिछले वित्तीय वर्ष के 5.96% से घट कर वर्ष 2009-10 में 5.09% रह गई, जबकि निधीयन लागत हेतु समायोजित अग्रिमों पर प्रतिलाभ उसी अवधि के 4.53% से घट कर 4.1% रह गया।

विनियामकों के कथन

नयी प्रणाली के तहत 41 यूनिट सम्बद्ध योजनाओं को इर्डा की मंजूरी मिली

यूनिट सम्बद्ध योजनाओं (ULIPs) के नये मानदंडों के प्रचलन में आ जाने के बाद बीमाकर्ताओं द्वारा 1ली सितम्बर, 2010 से लगभग 41 नयी यूनिट सम्बद्ध योजनाओं की शुरूआत की गई है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के अध्यक्ष श्री जे. हरि नारायण द्वारा यथा प्रदत्त सूचना के अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत 41 उत्पादों को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने बताया कि हमें 68 उत्पाद फाइलिंग प्राप्त हुई थीं, जिनके यूनिट सम्बद्ध योजनाओं के सम्बन्ध में हमारे हाल के दिशानिर्देशों के अनुरूप होने की आशा है। 41 फाइलिंग में, जिन्हे आज की तिथि तक मंजूरी दी जा चुकी है, दो पेंशन उत्पाद थीं।

नये बैंकों का वित्तीय समावेशन के लिए सुदृढ़ होना जरूरी

बैंकिंग क्षेत्र में नवागंतुकों को वित्तीय समावेशन को किफायती तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सुदृढ़ एवं अच्छी तरह पूंजीकृत होना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अभिलाषी बैंकों की पूंजीगत आवश्यकताओं सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श के दस्तावेज़ों के साथ बैंकिंग सहभागियों की संख्या बढ़ाने की अपनी प्रक्रिया आरंभ कर दी है, जिसके लिए जनता से प्रति-सूचना मंगवाई गई है।

लेनदेन लागत कम करने के लिए बैंकों से नयी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए कहा गया

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती के अनुसार भारत में प्रौद्योगिकी की पैठ बढ़ानी होगी और प्रति लेनदेन लागत में पर्याप्त रूप से कमी लानी होगी। डॉ. चक्रवर्ती, जिन्होंने बैंकों से उनकी कारबार प्रक्रियाओं, सुपुर्दगी मॉडेलों तथा उनके साथ ही सूचना प्रसंस्करण प्रणालियां बदलने के लिए व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (BPR) प्रणाली अपनाने का आग्रह किया, का कहना है कि "भारत में बैंकों की मध्यस्थीकरण लागत अब भी विकसित बैंकिंग बाज़ारों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लगती है। छोटे लेनदेनों की लागत में अभी तक कमी नहीं आई है। जब तक कम मूल्य वाले लेनदेनों को किफायती नहीं

बनाया जाता, कार्य-कुशलता पर्याप्त रूप से प्रभावित नहीं होगी।" बैंकों को प्रौद्योगिकी उन्नयन का पूरा लाभ उठाने के लिए समेकित एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्हें अपनी कारबार प्रक्रियाओं को
कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर के अनुसार पूर्णत: पुनर्विन्यस्त करना होगा। इस पुनर्विन्यास में उन नयी प्रणालियों का प्रभावी विधि से उपयोग करने के लिए, जो कर्मचारियों को फ्रंट ऑफिस कार्यों को निष्पादित करने हेतु मुक्त कर देंगी, नये

प्रक्रिया मैनुअलों का विकास करना तथा कार्मिकों को प्र शिक्षित करना शामिल होगा। डॉ. चक्रवर्ती ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि बैंकों के लिए उनकी सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना आवश्यक है, ताकि परिमाण, गुणवत्ता तथा कारबार की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए व्यापक ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन तकनीकें विकसित की जा सकें।

भारत को पूंजीगत लेखे की परिवर्तनीयता वाला मार्ग अपनाना चाहिए

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी सुब्बाराव यह महसूस करते हैं कि भारत को घरेलू और वैश्विक कारकों के अनुसार अंशाकित आधार पर पूंजीगत लेखे की परिवर्तनीयता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय रुपया चालू खाते पर पूर्णत: परिवर्तनीय है, किन्तु पूंजीगत लेखे पर केवल आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। डॉ. सुब्बाराव का कहना है कि "हमें एक रूपरेखा के साथ पूंजी लेखे की परिवर्तनीयता की दिशा में आगे अवश्य बढ़ना चाहिए, इस रूपरेखा को वैश्विक और घरेलू , दोनों ही प्रकार की घटनाओं पर निर्भर करते हुए गतिशील आधार पर अंशाकित होना चाहिए। पूंजी प्रवाहों को हमेशा अवश्य नियंत्रित रखा जाना चाहिए तथा भारत को शीघ्र ही एक बढ़ते हुए चालू खाते के घाटे से निपटना होगा, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से बढ़ रही है।"

बैंकों द्वारा बासेल III नियमों को पूरा किए जाने के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक विश्वस्त

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव का कहना है कि प्रस्तावित बासेल III नियमों द्वारा भारतीय बैंकों के महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने की संभावना नहीं है। 30 जून, 2010 के दिन भारतीय बैंकिंग प्रणाली का जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में कुल पूंजी का अनुपात 13.4% था, जिसमें से टियर- I पूंजी 9.3% थी। गवर्नर ने इस बात का उल्लेख किया कि यद्यपि बासेल III मानदंड अभी तक अंशांकित किए जाने हैं, इस बात की संभावना नहीं है कि वे इन आंकड़ों से अधिक होंगे। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय बैंक पहले से ही (पूंजी से) ऐसी अधिकांश कटौतियां करते आ रहे हैं, जो अब बासेल III के तहत प्रस्तावित की जा रही हैं, गवर्नर ने इस बात के प्रति आगाह किया कि कुछेक कटौतियों को टियर- I और टियर-II पूंजी से सामान्य इक्विटी में परिवर्तित किए जाने से उद्भूत होने वाले कतिपय नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

पुनर्खरीद (repo) दर का अंतर संकीर्ण किए जाने से अस्थिरता में कमी आएगी

डॉ. सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार पुनर्खरीद और प्रत्यावर्ती (reverse) पुनर्खरीद दरों के बीच अंतर को संकीर्ण किए जाने से एक-दिवसीय उधार दर प्रणाली में अस्थिरता में कमी आएगी। इस बात पर बल देते हुए कि मुद्रास्फीति अब भी केन्द्रीय बैंक के लिए चिंता का कारण बनी हुई है डॉ. गोकर्ण का कहना है कि " वर्तमान में स्थूल-आर्थिक स्थिति में एक आश्चर्यजनक प्रवृत्ति परिलक्षित हो रही है, जिसके द्वारा वैश्विक कीमतों में कमी आ रही है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में कीमतों को स्थिरता प्राप्त हो रही है।"

बैंकों को पीई, वीसी निधियों के लिए उच्चतर पूंजी मानदंडों का पालन करना होगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे कठोर मानदंड नियत करेगा, जिनमें पूंजी के बड़े निजी समूहों का प्रबन्धन करने वाले बैंकों के लिए अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं का समावेश हो सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर सुश्री उषा थोरात ने कहा है कि "जहां कोई बैंक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना नाम जोड़ता है अथवा पूंजी के बड़े निजी समूहों का प्रवर्तन / प्रबन्धन करता है, वहां परंपरागत ढांचे में शामिल न किए गए प्रतिष्ठा, संकेन्द्रण और अन्य जोखिमों का ध्यान रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी अपेक्षाओं की आवश्यकता है। यही कारण है कि हम पूंजी के बड़े निजी समूहों का प्रबन्धन करने वाले बैंकों के सम्बन्ध में दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर रहे हैं।" हालांकि, बैंक के निवेशों के प्रारंभिक सीमा से कम होने तथा निधियों के 20% से कम होने अथवा उसका नाम न जोड़े जाने की स्थिति में विशेष शर्तें निर्धारित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार के निवेशों को पूंजी बाज़ार के प्रति समग्र ऋण जोखिम (एक्सपोजर) की सीमा तथा पूंजी मानदंडों के भीतर ही रखना होगा।

वर्ष 2015 तक चल (मोबाइल) बैंकिंग में प्रत्येक गांव का समावेश होगा : भारतीय रज़र्व बैंक

डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2015 तक सभी गांवों का समावेश चल (मोबाइल) बैंकिंग में कर लिए जाने की योजनाएं जारी हैं। चल (मोबाइल) बैंक एक ऐसी सुविधा होती है, जिसमें किसी विशिष्ट बैंक के अधिकारियों के साथ एक प्राधिकृत वाहन किसी विशिष्ट गांव में एक विनिर्दिष्ट समय पर पहुंचता है। वह ग्रामवासियों को जमा एवं आहरण जैसी सीमित सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपयुक्त स्थान वाले गांवों में एक बैंक शाखा खोले जाने की एक रूपरेखा तैयार की थी। इसमें 2000 की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्रों को बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच की सुविधा प्राप्त होगी।

विदेशी मुद्रा विनिमय

अक्तूबर, 2010 माह के लिए लागू विमुअनि (बैंक)/ अनिवि
जमाराशियों की न्यूनतम दरें
12

अनिवि जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली (स्वैप दरें)

मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.77775	0.5950	0.8625		

विमुअनि (बैंक) जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली (स्वैप दरें)

मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली

	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.77775	0.595	0.863	1.151	1.484
ब्रिटिश पौण्ड	1.47078	1.2670	1.5220	1.7950	2.0500
यूरो	1.42000	1.472	1.634	1.799	1.960
जापानी येन	0.66000	0.401	0.411	0.441	0.496
कनाडाई डालर	1.92083	1.531	1.673	1.855	2.029
आस्ट्रेलियाई डालर	5.61375	5.220	5.270	5.440	4.490

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि

मद	24 सितम्बर, 2010 के दिन	20 सितम्बर, 2010 के दिन
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3
कुल आरक्षित निधियां	13,31,003	291,595
क) विदेशी मुद्रा में आस्तियां	12,04,664	264,529
ख) सोना	94,199	20,008
ग) विशेष आहरण अधिकार	23,148	5,083
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधि की स्थिति	8,992	1,975

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा व्यापारियों को काउंटर पर सौदे के रिपोर्टिंग मंच की सुविधा प्राप्त होगी

विदेशी मुद्रा व्यापारियों को शीघ्र ही मुद्रा विकल्प में काउंटर पर किए जाने वाले सौदों लिए भारत के पहले केन्द्रीकृत रिपोर्टिंग मंच तक पहुंच की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार का मंच क्रय-विक्रय किए गए विकल्प सौदों के परिमाणों और उसके साथ ही दरों का तात्कालिक डाटा उपलब्ध कराएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक से सिद्धांतत: अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (CCIL) काउंटर पर

किए जाने वाले सौदों के लिए ऐसा मंच विकसित करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहा है। इस घटना की पुष्टि करते हुए भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड की मुख्य विदेशी मुद्रा विनिमय अधिकारी सुश्री इंद्राणी राव का कहना है कि "उक्त मंच, जिसके द्वारा बैंक मुद्रा विकल्प लेनदेनों के सम्बन्ध में रिपोर्ट कर सकते हैं, काउंटर पर लेनदेन वाले बाज़ार में अत्यधिक आवश्यक पारदर्शिता लाने में सहायता करेगा। यह विनियामकों को विविध कम्पनियों की इस बाज़ार के प्रति एक्सपोजर के सम्बन्ध में सूचना भी उपलब्ध काराएगा। यह मंच वर्ष 2010-11 के दौरान तैयार हो जाएगा।" विदेशी मुद्रा व्यापारियों के अनुसार काउंटर पर किए जाने वाले सौदों के लिए रिपोर्टिंग मंच मुद्रा हाजिर बाज़ार में विदेशी मुद्रा की क्रय-विक्रय स्थिति का निर्धारण करने में उनकी सहायता करेगा।

रुपया ब्रिक क्लब में सर्वाधिक क्रय-विक्रय वाली मुद्रा

इस वर्ष भारतीय रुपया ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत और चीन) की अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक क्रय-विक्रय की जाने वाली मुद्रा तथा हांगकांग डालर और कोरियाई वोन के बाद तीसरी सबसे बड़ी एशियाई मुद्रा बन गया है। केन्द्रीय बैंक के सर्वेक्षण (जो बासेल, स्विटजरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय बैंक अर्थात् बीआईएस द्वारा तीन वर्ष में एक बार किया जाता है) से यह पता चला है कि सम्पूर्ण विश्व के सकल विदेशी मुद्रा विनिमय आवर्त में रुपये की रूस के साथ हिस्सेदारी 0.9% थी, जिसके बाद 0.7% अंश के साथ ब्राजील तथा 0.3% अंश के साथ चीनी रेनमिंबी का स्थान था।

पूंजी बाज़ार

सूचकांक के 20, 000 का स्तर पार करते ही बीएसई ने मोबाइल लेनदेन की शुरूआत की

जिस दिन सूचकांक 20, 000 का स्तर पार कर गया, उस दिन बंबई शेयर बाज़ार अपने मोबाइल लेनदेन मंच के साथ सक्रिय हो उठा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक माह से कम समय पहले ही बेतार (वायरलेस) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रतिभूतियों में लेनदेन का रास्ता साफ कर दिया था।

सूक्ष्मवित्त

सूक्ष्म वित्त कम्पनियों के बैंकों से सस्ती निधियों तक पहुंच की सुविधा खो बैठने की संभावना

श्री वी.के. शर्मा, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की एक समिति ने यह सिफारिश की है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की हैसियत, जो इस समय गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (NBFCs) के प्रति बैंकों के ऋण जोखिम (exposure) को प्रदान की जाती है, वापस ले ली जानी चाहिए। हालांकि, गैर-विघटनकारी और व्यवस्थित समापन अथवा निर्गम सुनिश्चित करने के लिए दल ने 31 मार्च, 2012 तक की समापन अवधि की सिफारिश की है। यद्यपि देश में सरकार द्वारा संचालित बैंकों ने भी उनकी ग्रामीण शाखाओं के माध्यम से सूक्ष्मवित्त संस्थाओं के प्रति प्रत्यक्ष ऋण जोखिम (exposure) वहन कर रखा है, अधिकांश निजी और विदेशी बैंक इस सुविधा का उपयोग उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु करते हैं। हालांकि, इस प्रकार के उधार (देने) में निहित लाभ बढ़ाने के अवसर को भांपते हुए कई एक विदेशी बैंक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार देने से सम्बन्धित अपने कार्य में अत्यधिक आक्रामक रहे हैं। कुछेक चुनिंदा लाभदायक एवं व्यावसायिक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को उधार देने के लिए बैंकरों के बीच आरंभ हो गई प्रतिस्पर्धा ने इनमें से कुछेक संस्थाओं की सौदेबाजी की शक्ति

बढ़ाने के अलावा प्रतिस्पर्धी दरों पर निधियां जुटाने में सहायता की है। हालांकि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वाला दर्जा वापस ले लिए जाने पर बैंक कारबार प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के पीछे पड़ने के प्रति उतने उत्साही नहीं रह जाएंगे।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

वैश्विक विदेशी मुद्रा विनिमय व्यापार बढ़ कर प्रति दिन 4 ट्रिलियन अमरीकी डालर हुआ

वैश्विक मुद्रा बाज़ारों में व्यापार पिछले तीन वर्षों में पांच गुने से अधिक बढ़ कर 4 ट्रिलियन अमरीकी डालर प्रति दिन हो गया। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा किए जाने वाले त्रि-वर्षीय सर्वेक्षण में इस वृद्धि को बचाव निधिया, बीमा फर्मों, केन्द्रीय बैंकों तथा अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की बढ़ती शक्ति द्वारा प्रेरित बताया गया है; जबकि इलेक्ट्रॉनिक मंच पर लेनदेन करने की सहूलियत से खुदरा लेनदेन की अपील बढ़ गई है। परिमाण में बढ़ोत्तरी परंपरागत हाजिर लेनदेनों के आवर्त में आए 48% के उछाल द्वारा प्रेरित थ, जिसे बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुद्रा बाज़ार के लेनदेनों के व्यापक आशुचित्र के रूप में गंभीरतापूर्वक देखा जा रहा है। हाजिर बाज़ार में हुई वृद्धि आंशिक रूप से प्रतीकगणितीय लेनदेन का निरूपण करती है, जिसमे तथाकथित काली पेटियां प्रति मिनट हजारों लेनदेनों को संसाधित कर सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के सर्वेक्षण, जिसमें 53 केन्द्रीय बैंकों और मौद्रिक प्राधिकरणों ने सहभागिता की थी, से यह पता चला है कि एक समय पर प्रबल माने जाने वाले अंतर बैंक व्यापारियों को पहली बार बचाव निधियों और केन्द्रीय बैंकों जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया।

नई नियुक्तियां

15

श्री अरुण कौल ने यूको बैंक के नये अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। यूको बैंक में सेवारंभ करने के पूर्व वे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री एस रामन ने केनरा बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे।

श्री रामनाथ प्रदीप को कारपोरेशन बैंक का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व वे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे।

सुश्री विजयलक्ष्मी आर. अय्यर ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की महा प्रबन्धक थीं।

श्री राजीव किशोर दुबे ने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे पंजाब नैशनल बैंक के महा प्रबन्धक थे।

श्री एस.एस. मूंदड़ा ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके पूर्व वे बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के महा प्रबन्धक थे।

श्री एन.आर. बद्रीनारायणन ने यूको बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवारंभ कर दी है। यूको बैंक में सेवारंभ करने के पूर्व वे बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के महा प्रबन्धक थे।

श्री ए.के. बंसल को इंडियन ओवरसीज़ बैंक (IOB) के नये कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व वे यूनयिन बैंक ऑफ इंडया के महा प्रबन्धक थे।

श्री पी. प्रदीप कुमार ने स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के प्रबन्ध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसके पूर्व वे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक के अमरीकी परिचालनों के प्रधान थे।

श्री ए.के. जगन्नाथन ने तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

श्री श्याम श्रीवास्तव ने दि फेडरल बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाल लिया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

सिबिल ने बंधक रखी हुई संपत्तियों के डाटाबेस की शुरूआत की

ऋण आसूचना ब्यूरों (भारत) लिमिटेड (CIBIL) और ट्रांसयूनियन ने राष्ट्रीय आवास बैंक के परामर्श से सिबिल बंधक जांच - बंधक से सम्बन्धित सूचना भंडार (repository) की शुरूआत की है। उक्त डाटाबेस में ऐसी संपत्तियों, जिन पर उनके स्वामियों ने ऋण ले रखा है, से सम्बन्धित सूचना, उन ऋणों के सारांश तथा उन संपत्तियों से सम्बन्धित व्यापक सूचना रखी जाएगी। इससे उधारदाताओं को बंधक से सम्बन्धित सूचना का आदान-प्रदान करने, उस तक पहुंचने, अपेक्षाकृत सुदृढ़ यथोचित कर्तव्यपरायणता बरतने तथा कपटपूर्ण लेनदेनों में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।

आईसीआईसीआई और किंगफिशर ने क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की

आईसीआईसीआई बैंक ने किंगफिशर एअरलाइन्स के साथ मिल कर एक ऐसे नये क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की है, जो उसके धारकों को जीवन-शैली से सम्बन्धित प्रसुविधाएं प्रदान करता है। आईसीआईसीआई बैंक - किंगफिशर एअरलाइन्स का मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड धारक को कार्ड पर किए जाने वाले सभी खर्चों के लिए त्वरित मील भत्ता, उक्त सुविधा में शामिल होने और उसे नवीकृत कराने हेतु बोनस मील भत्ता, मानार्थ कोटि-उन्नयन, वाउचर तथा किंग क्लब की सदस्यता प्राप्त करने में समर्थ बनाता है।

भारतीय स्टेट बैंक ने मुंबई में कियॉस्क बैंकिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की

भारतीय स्टेट बैंक ने महाराष्ट्र में कियॉस्क बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी कम्पनी ऑक्सीजन सर्विसेज के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की है। प्रारंभ में बैंक मुंबई में 50 बिक्री केन्द्रों की शुरूआत कर रहा है, जिनमें से पहला केन्द्र धारावी में होगा।

यूनाइटेड इंडिया ने कार्पोरेशन बैंक के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस ने कार्पोरेशन बैंक के साथ सूक्ष्म बीमे तथा अन्य ग्रामीण बीमा उत्पादों का बैंक के कारबार संपर्कियों के माध्यम से वितरण करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है।

ह्युंडई ने कार वित्तीयन के लिए विजया बैंक के साथ गंठजोड़ किया

ह्युंडई मोटर इंडिया ने अपने क्रेताओं को खुदरा वित्तीयन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विजया बैंक के साथ गंठजोड़ किया है। ह्युंडई मोटर इंडिया के निदेशक (विपणन एवं बिक्री) श्री अरविंद सक्सेना का कहना है कि "इस सहयोग के परिणामस्वरूप हम अपने प्रसार क्षेत्र को बेहतर और अपेक्षाकृत सरल वित्तीय विकल्पों के साथ व्यापक ग्राहक आधार तक बढ़ाने में समर्थ होंगे। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी दरें और बैंक की सहजता से पहुंचयोग्य अवस्थितियों का हमारे ग्राहकों को निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा।" समझौता ज्ञापन के
तहत दोनों ही भागीदार बैंक के कार ऋणों और योजनाओं के साथ ही ह्युंडई के वाहनों की प्रति-बिक्री करने के लिए एक-दूसरे की शक्तियों का उपयोग करेंगे तथा उनका लाभ उठाएंगे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने यूआईडीएआई के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया

पंजाब ऐण्ड सिंध बैंक ने भारतीय अनन्य पहचान पत्र प्राधिकरण (UIDAI) के साथ उनकी अनन्य पहचान पत्र परियोजना आधार के लिए पंजीयक के रूप में कार्य करने हतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इस करार

के तहत लगभग 65 लाख के ग्राहक आधार वाला बैंक अपने खाता धारकों तथा उनके साथ ही साथ भावी ग्राहकों के (अनन्य पहचान पत्र मानदंडों के अनुसार) जीवसांख्यिकीय एवं जनांकिकीय
(biometric and demographic) विवरण एकत्रित करेगा। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री पी.के. आनंद ने कहा है कि बैंक त्वरित एवं सहज पंजीकरण सुनिश्चित करेगा, जो परियोजना के यथेष्ट रीति से पूरी किए जाने हेतु आवश्यक होगा। पंजाब एण्ड सिंध बैंक की पूरे देश में 924 शाखाएं हैं, जिनमें से 325 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

सिडिकेट बैंक और विजया बैंक ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए

सिडिकेट बैंक और विजया बैंक ने पूरे कर्नाटक में स्थित अग्रणी बैंक जिलों तथा आगे चल कर देश के अन्य राज्यों में विस्तारित किए जाने वाले वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करने के लिए ज्ञान ज्योति वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श न्यास (JJFLCCT) गठित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

संस्थान समाचार

संपर्क कक्षाएं

आंचलिक कार्यालयों द्वारा आगामी जेएआईआईबी / सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए संपर्क कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया http:// www.iibf.org.in देखें तथा आंचलिक कार्यालयों से संपर्क करें।

अनुपालन पर कार्यशाला

संस्थान इंटरनेशनल कम्प्लाएंस एसोसिएशन, लंदन के सहयोग से 20 से 23 अक्तूबर, 2010 तक की अवधि के दौरान नई दिल्ली और बंगलूरू में अनुपालन पर दो द्वि-दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है।

जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परिणाम सूचनाओं का प्रेषण

संस्थान ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने जेएआईआईबी / सीएआईआईबी परीक्षा के सभी विषय उत्तीर्ण कर लिए हैं, समेकित अंकपत्र व समापन ज्ञापन जारी करेगा। जहां तक उन अभ्यर्थियों का सम्बन्ध है, जिन्होंने सभी विषय नहीं उत्तीर्ण किए हैं, मुद्रित परीक्षाफल सूचनाएं (मूल और उसके साथ ही साथ उसकी अनुलिपि) नहीं जारी की जाएंगी, किन्तु वे संस्थान की वेबसाइट पर मुद्रणीय रूप में उपलब्ध होगी। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे उसे हमारी वेबसाइट' www.iibf.org.in' से डाउनलोड कर लें।

महत्वपूर्ण दरें / अनुपात

बैंक दर	8.00 %
पुनर्खरीद (Repo) दर (16 सितम्बर, 2010 से प्रभावी)	6.00 %
प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद (reverse repo) दर (16/9/2010 से प्रभावी)	5.00 %
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	6.00 %
सांविधिक चलनिधि अनुपात	25.00 %

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 / दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

बढ़ता इक्विटी बंधक

नियत दर वाला ऐसा बंधक जिस पर एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कुछ समय बाद मासिक भुगतान बढ़ते रहते हैं। ऋण पर ब्याज दर नहीं बदलती तथा किसी प्रकार नकारात्मक ऋण परिशोधन कभी नहीं होता। दूसरे शब्दों में पहला भुगतान पूर्णत: परिशोधक भुगतान होता है। जैसे-जैसे भुगतान बढ़ते जाते हैं, पूर्णत: परिशोधक भुगतान की रकम से अधिक एवं परे अतिरिक्त रकम बंधक के जीवनकाल को कम करते हुए तथा ब्याजगत बचतों को बढ़ाते हुए बंधक की शेष बची रकम मे प्रयुक्त कर ली जाती है।

शब्दावली

आधा बंद बटुआ (थैला)

आधा बंद बटुआ (थैला) ग्राहकों को वास्तविक नकदी का ऐसी आभासी मुद्रा में विनिमय करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे मोबाइल फोन पर भण्डारित किया जा सकता है। इसका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा 5,000 रुपये तक के सामानों एवं की खरीद हेतु किया जा सकता है।

बाज़ार की खबरें

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

20500
20000
19500
19000
18500
18000
17500
17000
17700

20

03/09/10 06/09/10 09/9/10 13/09/10 14/09/10 15/09/10 16/09/10 17/09/10
20/09/10 21/09/10 22/09/10 24/09/10 27/09/10 29/09/10 30/09/10

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

78
73
68
63
58
53
48

02/09/10 06/09/10 07/09/10 09/09/10 13/09/10 17/09/10 20/09/10 21/09/10
22/09/10 27/09/10 29/09/10 30/09/10

अमरीकी डालर यूरो जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- चूंकि एशियाई आर्थिक आंकड़ों में निहित शक्ति ने इस चिंता को कम कर दिया कि वैश्वक पुनरुत्थान लड़खड़ा रहा है तथा अपेक्षाकृत अधिक जोखिमपूर्ण उभरते बाज़ारी आस्तियों की मांग में तेजी ला दी, दो माह से अधिक की अवधि में सर्वाधिक अभिलाभ के साथ 46.81 रुपये प्रति डालर की दर से 0.6% की वृद्धि।
- 2 सितम्बर को रुपया 0.2% बढ़ कर 46.72 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
- एक सप्ताह पहले के 46.72 रुपये के स्तर से रुपया 0.5% बढ़ गया।
- 13 सितम्बर को रुपया 0.2%बढ़ कर प्रति डालर 46.30 रूपये के स्तर पर पहुंच गया।
- 15 सितम्बर को रुपया पुन: 2% बढ़ कर 46.30 के स्तर पर पहुंच गया। बाज़ार के विश्लेषकों का कहना है कि निरंतर एवं सुदृढ़ पूंजी अंतर्वाहों के कारण, यहां रुपये में मूल्यवृद्धि की सुश्पष्ट प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।
- 17 सितम्बर को रुपया तीन माह में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच कर 45.84 रुपये के समकक्ष हो गया।
- 27 सितम्बर को विदेशी निवेशकों द्वारा एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में हुई वृद्धि से लाभ उठाने के प्रयास में स्थानीय इक्विटियों की खरीद तीव्र कर दिए जाने के बाद रुपया चार माह से अधिक

की अवधि में बढ़ कर अपने सुदृढ़तम स्तर पर पहुंच गया। रुपया 0.5% की मूल्यवृद्धि के साथ प्रति डालर 45.01 रुपये पर पहुंच गया।

भारित औसत मांग दरें

7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00
4.50
4.00

01/09/10 02/09/10 03/09/10 06/09/10 07/09/10 09/09/10 13/09/10 14/09/10
16/09/10 17/09/10 18/09/10 20/09/10 24/09/10 25/09/10 28/09/10 29/09/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, सितम्बर, 2010
मांग दर 6% पर पहुंच गई; बैंकों ने 46,000 करोड़ के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क किया।

बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से 46,000 करोड़ रुपये लिये जाने के बावजूद प्रणाली में मुद्रा की कमी ने मांग दरों को 6% के स्तर के आगे पहुंचा दिया। मांग दरें, जो सितम्बर के मध्य से लगभग 6% पर स्थिर थीं, 6.18% पर बंद हुईं। अग्रिम करों के वहिर्वाह, जिसने बैंकिंग प्रणाली से लगभग 40, 000 करोड़ रुपये अवशोषित कर लिया, के कारण मुद्रा बाज़ार में मंहगी व्याप्त रही।

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न अक्तूबर, 2010

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये

(आईएसओ 9001 : 2000 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 3 अंक सं. : 04 नवम्बर 2010

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

भारतीय रिज़र्व बैंक ----------1
मुख्य घटनाएं---------- 2
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------3
बैंकिंग जगत की घटनाएं----------3
विदेशी मुद्रा----------5
विनियामकों के कथन ----------5
पण्य (जिंस) बाज़ार----------5
अंतरराष्ट्रीय समाचार----------5
नयी नियुक्तियां----------6
उत्पाद एवं गंठजोड----------6
सूक्ष्मवित्त ----------6
संस्थान समाचार----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---------- 7
शब्दावली ----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति 2010-11 की 2री तिमाही की समीक्षा

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 6.00 प्रतिशत पर कायम रखी गई।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (Repo) दर 6.00% से 25 आधार अंक बढ़ा कर 6.25% कर दी गई।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रत्यावर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 5.00% से 25 आधार अंक बढ़ा कर 5.25% कर दी गई।
- आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 6% पर कायम रखा गया।
- आवास ऋणों की उच्चतम सीमा संपत्ति के मूल्य के 80% पर नियत कर दी गई।
- 75 लाख रुपये से अधिक के गृह ऋणों का जोखिम-भार 25 आधार अंक बढ़ा दिया गया।
- आवासीय ऋणों पर टीजर दरों के लिए प्रावधानीकरण बढ़ा कर 2% कर दिया गया।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 3 से टियर 6 तक वाले केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाएगी।

- वित्तीय समूहों (conglomerates) की पूंजी पर्याप्तता से सम्बन्धित मानदंड कठोर बनाए गए।

घरेलू परिदृश्य

आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि सुस्थिर बनी रही। वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही की 8.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि से यह पता चलता है कि अर्थव्यवस्था, अधिकांशतया घरेलू कारकों से प्रेरित हो कर प्रवृत्ति के अनुरूप वृद्धि की निकटवर्ती दर पर परिचालित हो रही है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के संकेतक स्थिर वृद्धि का संकेत करते हैं।

मुद्रास्फीति महत्वपूर्ण रूप से अपनी मध्यावधिक प्रवृत्ति से अधिक के स्तर पर कायम है। जहां खाद्येतर विनिर्मित उत्पादों से सम्बन्धित मुद्रास्फीति स्थिर हो गई है, वहीं खाद्यपदार्थों से सम्बन्धित मुद्रास्फीति में मानसून के बाद वाला अपेक्षित संयमन नहीं परिलक्षित होता। यह चिंता का कारण है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था में प्रवृत्ति के आसपास वाली वृद्धि हो रही हो, संरचित खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित मुद्रास्फीति के जोखिमों का अन्य वस्तुओं की कीमतों में फैल जाना महत्वपूर्ण घटना है और वह संभाव्य रूप से हाल के संयमन का प्रतिकार कर सकती है।

वैश्विक बाज़ार

उक्त समीक्षा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में व्याप्त चिरस्थायी मंदी और उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं से प्राप्त होने वाले सकारात्मक संकेतों के संदर्भ में प्रवर्तित है। जहां वर्ष 2010 के द्वितीयार्ध में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पुनरुत्थान की गति धीमी पड़ गई है, वहीं उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देने का क्रम जारी है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में पुनरुत्थान की नाजुक और विषम प्रकृति और व्यापक बेरोज़गारी वैश्विक पुनरुत्थान की स्थिरता के प्रति चिंता पैदा करती है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को वर्ष 2010 के 4.8% की तुलना में वर्ष 2011 में 4.2% के विश्वव्यापी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का कमतर अनुमान लगाने हेतु प्रेरित किया। पुनरुत्थान की मंद होती गति के प्रति बढ़ती चिंताओं ने कुछेक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केन्द्रीय बैंकों को निजी मांग को और अधिक प्रेरित करने हेतु मात्रात्मक सहूलियतों का एक और दौर आरंभ करने हेतु प्रेरित किया। जहां उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की 'अति-शिथिल' मौद्रिक नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था को मध्यावधिक दृष्टि से लाभ हो सकता है, वहीं अल्पावधिक दृष्टि से जिंसों की वैश्विक कीमतों में ऊर्ध्वमुखी दबाव निर्मित होगी।

मुख्य घटनाएं

एकदिवसीय ब्याज अदला-बदली दरें दो वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के प्रबन्ध निदेशक और दक्षिण एशिया के लिए दरों के प्रधान श्री अनंत नारायण ने बताया कि "एक वर्ष वाली एक-दिवसीय ब्याज दर अदला-बदली (swap) से सम्बन्धित दर (OIS) अथवा उधार लेने की लागतों में होने वाले उतार-चढ़ावों से संरक्षित रखने हेतु प्रयुक्त होने वाली व्युत्पन्नी संविदाएं 6.64% के दो वर्षों के उच्चतर स्तर तक बढ़ गईं, जो अक्तूबर 2008 से, जब यह 6.58% की दर पर क्रय-विक्रय की जा रही थी, ब्याज दरों में होने वाली वृद्धि का अब तक का सर्वोच्च स्तर है।"

एएनजेड मुंबई में शाखा खोलेगा

आस्ट्रेलिया के अग्रणी बैंक एएनजेड को वर्ष 2011 के प्रथमार्ध में मुंबई में एक शाखा खोलने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

आईएफआरएस लागू किए जाने से पहले लेखांकन मानदंड आशोधित किए जा सकते हैं

राष्ट्र के विश्वव्यापी स्तर पर मान्यता प्राप्त लेखांकन प्रणाली की दिशा में प्रस्थान करने में छ: महीनों से भी कम समय रह जाने के परिणामस्वरूप सरकार विदेशी मुद्रा और विदेशी उधार राशियों के बीच अन्तरों से सम्बन्धित कुछेक मुख्य प्रावधानों को आशोधित करना चाहती है। विदेशी मुद्रा के उन अंतरों के मामले में, जो फर्मों द्वारा ली जाने वाली मुद्रा व्युत्पन्नियों के कारण उद्भूत होते हैं, सरकार उस विकल्प को अपनाना चाहती है, जिसमें कम्पनियों के लिए लाभ एवं हानि विवरण में किसी प्रकार की हानि का प्रावधान करना जरूरी नहीं होता, अपितु उसके बजाय मार्च 2011 के अंत में केवल मूल्य को आगे ले जाना होता है।

बैंकों को लाइसेंस : इंडिया इंक अवसर का लाभ उठाने हेतु तत्पर

टाटा, आदित्य बिड़ला समूह, महिन्द्रा, लार्सन एण्ड ट्यूब्रो तथा रेलिगेयर जैसे सबसे बड़े व्यासायिक गृह बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु अपने अवसरों को मज़बूत बनाने के लिए अपने निदेशक मंडलों में बैंकिंग क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को शामिल कर रहे हैं, जिससे सम्बन्धित मानदंडों के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शीघ्र ही घोषित किए जाने की आशा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 3 वर्षों में 85, 000 स्टाफ सदस्य भर्ती करेंगे

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जनशक्ति की कमी को पूरा करने हेतु आगामी 3 वर्षों में लगभग 85, 000 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रखी है। सरकार का कहना है कि "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 2010-2013 के दौरान लगभग 34, 000 अधिकारियों और 51, 000 लिपिकों की भर्ती करने की

एक कामचलाऊ योजना तैयार कर रखी है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) के माध्यम से भर्ती की यह प्रणाली पारदर्शी, द्रुत गतिवाली एवं किफायती होगी।"

वीसा को निधि विप्रेषण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति मिली

एक अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रौद्योगिकी फर्म, वीसा को भारत में जारी पात्र वीसा डेबिट अथवा पूर्व-प्रदत्त कार्डों को आवक सरहद-पार वाले विप्रेषणों की सुविधा प्रदान करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति भारत की एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक कार्ड भुगतान प्रौद्योगिकी कम्पनी वीसा को आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक सहित 40 से अधिक बैंकों की सहायता करने में समर्थ बनाती है।

यूनियन बैंक नकदी-रहित कैंपस का लाभ उठाएगा

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के लगभग 2, 500 छात्र विश्वविद्यालय में जाने और कतारों में खड़े रहने के बजाय एक मोबाइल बिक्री केन्द्र (POS) उपकरण के माध्यम से कैम्पस में ही भुगतान कर रहे हैं। उन्हें मोबाइल ले जाने की भी जरूरत नहीं होती, वे केवल अपने मोबाइल की पिन तथा कैम्पस में लगे बिक्री केन्द्र (POS) उपकरण पर मौजूद संख्या का उपयोग करते हुए लेनदेन कर सकते हैं। यह मोबाइल बैंकिंग सेवा, जिसने मध्य प्रदेश राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय को समय-साध्य नकदी एवं चेक लेनदेनों की अड़चन से मुक्त कर दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सितम्बर में आरंभ की गई 'नकदी-रहित कैम्पस' परियोजना का ही एक अंग है।

यूनियन बैंक, जो दो वर्ष पहले भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसे अनुमति प्रदान किए जाने के बाद, विकास/ वृद्धि के अगले स्तर तक पहुंचने के लिए प्रौद्योगिकी लाभ उठाने का प्रयास करते हुए मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने वाला पहला बैंक है। बैंक ने कारबार मॉडेलों एवं प्रणालियों को नवोन्मेषित करने में लगभग 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

नये बैंक के लाइसेंस इसी वित्तीय वर्ष में

वित्तीय सेवाओं के सचिव श्री आर. गोपालन द्वारा यथाप्रदत्त रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्रालय को आशा है कि नये बैंक लाइसेंसों का पहला सेट आगामी कुछेक महीनों में जारी कर दिया जाएगा। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों में विदेशी धारिता के सम्बन्ध में 74% की सीमा को बनाए रखे जाने पर सहमति व्यक्त की है। नये बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में इस वर्ष के अगस्त माह में तैयार किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के दस्तावेज़ में विदेशी स्वामित्व के संभाव्य संकेन्द्रण से बचने के लिए एक प्रस्ताव

समग्र विदेशी धारिता पर सीमा को 74% से घटा कर 50% करने से सम्बन्धित था। इसके अलावा, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से सम्बन्धित नीति में यह निर्धारित किया गया है कि किसी विदेशी बैंक की पूर्णत: स्वाधिकृत

सहायक कम्पनी को छोड़कर किसी निजी क्षेत्र वाले बैंक में प्रदत्त (चुकता) पूंजी का कम से कम 26% अंश हर समय निवासियों द्वारा धारित होगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नाबार्ड में निहित हित सरकार के पक्ष में छोड़े

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) में निहित कुल 1, 430 करोड़ रुपये मूल्य के अपने हित (जोखिम) सरकार के पक्ष में छोड़ दिए। इस वंचन के बाद नाबार्ड में केन्द्रीय बैंक की शेयरधारिता घट कर 1% हो गई है, जबकि भारत सरकार की शेयरधारिता 99% है। इसके परिणामस्वरूप नाबार्ड में सरकार का वर्चस्व तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उसके ऋण सम्बन्धी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निर्देश जारी का लोच अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगा।

विदेशी बैंकों के लिए स्थानीय निगमन जरूरी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी बैंकों की शाखाओं के पूर्णत: स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों में परिवर्तन से सम्बन्धित अपने विचार-विमर्श दस्तावेजों का प्रारूप वित्त मंत्रालय को भेज दिया है। उक्त प्रारूप में विदेशी बैंकों के लिए वर्धित बाज़ार पहुंच के साथ अनिवार्य स्थानीय निगमन की सिफारिश की गई है। बताया जाता है कि उक्त प्रारूप मंत्रालय को भेज दिया गया है, क्योंकि विदेशी बैंकों को लाइसेंस प्रदान किया जाना एक द्विपक्षीय मुद्दा भी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के इस बात पर बल दिए जाने पर कि विदेशी बैंक स्थानीय स्तर पर निगमन कराएं, इस बात की संभावना नहीं है कि इसका अधिक प्रतिरोध हो। विश्वव्यापी वित्तीय संकट के बाद, विश्व-भर के विनियामक यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक अन्य वित्तीय संकट पैदा होने पर स्थानीय व्यवसाय प्रभावित न हों, स्थानीय निगमन पर बल दे रहे हैं। प्रसंगवश, भारत में उपस्थिति रखने वाले बैंकों के मामले में इस प्रकार का संरक्षण पहले से मौजूद है। एक बैंकर का कहना है, "यहां तक कि विदेशी बैंकों की शाखाओं के लिए भी स्थानीय स्तर पर पूंजी बनाए रखना तथा पूंजी पर्याप्तता एवं ऋण जोखिम (exposure) सीमा से सम्बन्धित विवेकसम्मत दिशानिर्देशों को पूरा करना जरूरी है। भारत में परिचालनरत अधिकांश बैंकों के लिए स्थानीय स्तर पर निगमन का अर्थ होगा आस्तियों को अंतरराष्ट्रीय संस्था / कम्पनी से एक स्थानीय कम्पनी को हस्तांतरित करते हुए कानूनी ढांचे को बदलना।"

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वेतन खाते खोलने से सम्बन्धित नियम कठोर बनाया

7

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वेतनभोगियों के बैंक खाते खोलते समय नियोक्ताओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा उपयोगिता बिलों जैसे एक और प्रमाण मांगने का निर्देश दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक यह महसूस करता है कि दो प्रलेखों पर बल दिए जाने से खाते के दुरुपयोग के अवसरों में कमी आएगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक का स्वैच्छिक रूप से परिवर्तनीय दस्तावेज़ों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की हैसियत देने से इनकार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्वैच्छिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा अधिमान शेयरों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) का ही एक अंग माने जाने की अनुमति दिए जाने से सम्बन्धित औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि स्वैच्छिक रूप से परिवर्तनीय लिखत, जिनमें कीमत-निर्धारण (कुछेक मानकों के आधार पर) किसी भावी तिथि को किया जाता है, निवेशकों को ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी जोखिम से संरक्षित करते हैं और इसलिए उन्हें केवल इक्विटी के बजाय ऋण माना जाना चाहिए। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा जारी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से सम्बन्धित समेकित मानदंडों में (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन) कार्यरत उस नोडल एजेन्सी, जो विदेशी निवेशों के लिए दिशानिर्देश तैयार करती है, ने यह सुझाव दिया था कि कुछेक निश्चित मानकों के आधार पर परिवर्तन-कीमत को किसी भावी तिथि को नियत किए जाने के विकल्प वाले अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों (CCDs) और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयरों (CCPs) को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश माना जाए।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

अर्थव्यवस्था में कायापलट

कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था (CDR) तंत्र में शामिल समस्यामूलक ऋण की मात्रा में अप्रैल - सितम्बर की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले तीव्र गिरावट आई, जिससे अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक कायापलट और व्यावसायिक वातावरण में सुधार का पता चलता है। कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था से सम्बन्धित आंकड़ों के अनुसार बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं ने जुलाई - सितम्बर की अवधि में वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही के 7, 919.53 करोड़ रुपये की तुलना में 2, 469.08 करोड़ रुपये के ऋण जोखिम (एक्सपोजर) वाले 12 मामले भेजे। अप्रैल - जून की अवधि में स्वीकृत ऋणों का मूल्य 2, 563.71 करोड़ रुपये था। वर्ष 2009-10 की पहली तिमाही में मंच द्वारा 7, 603.40 करोड़ रुपये से सम्बन्धित 14 मामले स्वीकार किए गए थे।

अल्प - अवधि वाली प्रतिभूतियों की अच्छी-खासी मांग

8

गौण बाज़ार में अपेक्षाकृत कम अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs) की मांग थोड़ी बढ़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि बैंक 1 से 3 वर्ष वाली प्रतिभूतियों में निवेश करने को तरजीह देते हैं। बैंकों के लिए यह बढ़ती ब्याज दर वाले परिदृश्य में उनके निवेश संविभाग में हानियों को न्यूनतम रखने का एक उपाय होता है। बैंकों को 25% का सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) बनाए रखना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों में आवश्यक रूप से निवेश करना होता है। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफलों में वृद्धि की प्रवृत्ति मौजूद है, क्योंकि ऐक्सिस बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रधान, बाज़ार श्री आर.वी.एस. श्रीधर द्वारा यथा-उल्लिखित रूप में सहभागियों को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा नवम्बर में की जाने वाली अर्ध-वार्षिक समीक्षा में अपनी कठोर मौद्रिक नीति को जारी रखे जाने की आशा है।

1ली तिमाही में चालू खाते का अंतर बढ़ कर 13.7 बिलियन अमरीकी डालर

अपेक्षाकृत अधिक व्यापार घाटे और कमतर निवल अदृश्य भुगतानों के परिणामस्वरूप अप्रैल - जून, 2010 की अवधि में चालू खाते का घाटा बढ़ गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी भुगतान संतुलन से सम्बन्धित आंकड़ों के अनुसार चालू खाते का घाटा वर्ष 2010-11 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4.5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ कर 13.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। अदृश्य भुगतानों में 35.5% की वृद्धि हुई, जिससे वे (16.4 बिलियन अमरीकी डालर के समक्ष) 22.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गए। इसके विपरीत अदृश्य प्राप्तियों में केवल 13.6% की वृद्धि हुई तथा वे (37.6 बिलियन अमरीकी डालर के समक्ष) 42.7 बिलियन अमरीकी डालर रहीं। इसके फलस्वरूप निवल अदृश्य राशियों (अदृश्य प्राप्तियां घटाएं अदृश्य भुगतान) में 3.4% की मामूली गिरावट आई तथा वे 20.5 बिलियन अमरीकी डालर (21.2 बिलियन अमरीकी डालर) रहीं। पहली तिमाही में अदृश्य भुगतानों में हुई वृद्धि निवेशगत आय के तहत अधिक भुगतानों के कारण तथा यात्रा, परिवहन व्यय, व्यवसाय एवं वित्तीय सेवाओं के कारण अपेक्षाकृत अधिक थी।

समावेशन अभियान से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को और अधिक सरकारी निधियां

सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कम से कम केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास जमाराशियों का न्यायसंगत अभिनियोजन हो। वित्त मंत्रालय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाना चाहता है तथा उसने उन्हें वित्तीय एवं प्रौद्योगिकीय सहायता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये की एक निधि गठित कर रखी है। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यह निदेश दिया है कि वे वर्षांत तक अनर्जक आस्तियों (NPAs) अथवा अशोध्य ऋणों के स्तर को घटा कर अपनी आस्तियों के 5% से कम के स्तर पर लाएं और वित्तीय समावेशन की रूपरेखा को भी अंतिम रूप प्रदान कर दें। "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से वित्तीय समावेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए

जाने की अपेक्षा है। सरकारी योजनाओं में उन्हें एक अंश दिए जाने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि लाभ इस श्रृंखला के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें।"

9

दूसरी तिमाही में ऋण की मांग और जमा-वृद्धि धीमी

दूसरी तिमाही (24 सितम्बर तक) में बैंकों ने कुल 19,902 करोड़ रूपये के ऋण संवितरित किए, जो पहली तिमाही की ऋण वृद्धि के 1.62 लाख करोड़ के आंकड़ों से काफी कम है। पिछली तिमाही में ऋणों की संख्या प्राथमिक तौर पर 3 जी और व्यापकबैंड बेतार पहुंच स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने वाली दूरसंचार कम्पनियों से निधियों की मांग के कारण बढ़ गई थी।

ऋण की द्रुत गति से बढ़ती मांग वाले परिदृश्य ने बैंकरों को भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सूचित करने हेतु प्रेरित किया कि इस वित्तीय वर्ष में ऋण वृद्धि में उसके लिए नियत लक्ष्य की तुलना में 20% की कमी हो सकती है। दूसरी तिमाही में बैंकों की जमाराशियों में पिछली तिमाही के 1, 46, 130 करोड़ रुपये की तुलना में 74, 509 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । अपनी मौद्रिक नीति की मध्य-तिमाही समीक्षा में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस आशय की चेतावनी दी कि नकारात्मक वास्तविक दरों का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि बैंकों को जमा वृद्धि में कमी का सामना पड़ा, क्योंकि बचतकर्ता किसी अन्य स्रोत से अपेक्षाकृत अधिक प्रतिलाभ की ताक में थे। यदि बैंक ऋण को वृद्धि में बाधक नहीं बनना है, तो वास्तविक दरों को बैंक जमाराशियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में ले जाना होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के क्षेत्र में हस्तक्षेप की तैयारी के कारण चलनिधि में दुर्लभता की स्थिति

अंतर-बैंक मुद्रा बाज़ार में चलनिधि एक बार पुन: दुर्लभ होती जा रही है, जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक उधारदाता की भूमिका निभाने के लिए विवश हो गया है। बैंकों ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) से सम्बन्धित अपनी अपेक्षाएं पूरी करने हेतु 77, 935 करोड़ रुपये जितनी भारी मात्रा में उधार ले रखा है। कुछेक बैंकरों का मानना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार में संभाव्य हस्तक्षेप से पहले चलनिधि की स्थिति कठोर बनाए हुए है, उसके डालरों की खरीद आरंभ कर देने पर, भारतीय रिज़र्व बैंक अंतर-बैंक बाज़ार में रुपयों की बाढ़ ला देगा।

पिछले कुछेक सप्ताहों से मुद्रा बाज़ार से अधिशेष नकदी धीरे-धीरे गायब होती जा रही है। सितम्बर के अंतिम सप्ताह में उधार राशियां अग्रिम कर बहिर्वाहों की पृष्ठभूमि में 89, 925 करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गईं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कोषपाल श्री संजय आर्य के अनुसार "यदि भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करता ही है, तो उससे चलनिधि की स्थिति थोड़ी सहज होगी। हमें सरकारी खर्चों के भी प्रणाली में आने की आशा है।"

ग्रामीण, सहकारी बैंकों के ग्राहकों को शीघ्र ही एटीएम सुविधा

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) और अन्य सहकारी बैंकों के ग्राहक कुछ ही महीनों में देश भर में स्थित लगभग 63,000 एटीएमों में से किसी भी एक से नकदी आहरित करने तथा शेष राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) एकल आधार वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कोर बैंकिंग समाधान (CBS) मंच तथा एटीएम स्विच वाले सहकारी बैंकों को एक ऐसे प्रायोजक बैंक के माध्यम से जुड़ने की सुविधा प्रदान करेगा, जो राष्ट्रीय वित्तीय स्विच से पहले से ही जुड़ा हो। मुख्य धारा वाले बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों की संभाव्य जोखिमों के लिए प्रोफाइल तैयार करने के बाद, इन बैंकों के ग्राहकों को अखिल भारतीय एटीएम संयोजकता (connectivity) प्रदान करने हेतु अपने उप-सदस्यों के रूप में नामांकन कर सकते हैं।

खाद्येतर ऋणों का उठाव 20.13% बढ़ा।

खाद्येतर ऋण अथवा धन की वह रकम जो बैंक कारपोरेटों और व्यक्तियों को उधार देते हैं, वर्षानुवर्ष 20.13 क दर से बढ़ा और वह 8 अक्तूबर, 2010 को समाप्त पखवाड़े के दौरान 34, 19, 244. 54 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह वृद्धि 24 सितम्बर, 2010 को समाप्त पिछले पखवाड़े में दर्ज वृद्धि की तुलना में लगभग 140 आधार अंक अधिक है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों से यह पता चलता है कि बैंकों ने इस पखवाड़े के दौरान 47,185.4 करोड़ रुपये का अधिक उधार दिया। कुल बकाया ऋण, जिसमें वर्षानुवर्ष 20.07% की वृद्धि दर्ज हुई, 34, 68, 998.94 करोड़ रुपये रहा।

बैंकों ने 89, 9000 करोड़ रुपये उधार लिये; सीपी और सीडी दरें बढ़ीं

यद्यपि प्रणाली में ऋण का उठाव नहीं हो रहा है, फिर भी बैंकों ने अल्पावधिक चलनिधि की कमी से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्खरीद (Repo) सुविधा से 89,9000 करोड़ रुपये उधार लिये। निकट अतीत में एक-वर्षीय जमा प्रमाण पत्र (CDs) की दरों में लगभग 33 से 35 आधार अंकों की वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप उनका क्रय-विक्रय 7.50% पर हो रहा है, जबकि 4 माह वाले वाणिज्यिक पत्रों (CPs) की दरों में प्राय: 50 आधार अंकों की वृद्धि हुई, जिससे वे 7.62% पर क्रीत-विक्रीत हो रहे हैं। जहां एक-दिवसीय मांग दर को 6.10%- 6.45% की श्रेणी में भ्रमण करते देखा गया, यह कमोबेश अपरिवर्तित रही।

जमाकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने भी दरें बढ़ाईं

अधिकांश बैंकों द्वारा जमा दरों में वृद्धि कर दिए जाने के परिणामस्वरूप आवास वित्तीयन कम्पनियों तथा गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कम्पनियों सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां भी बचतकर्ताओं को रिझाने के लिए जमाराशियों पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दर प्रदान करने पर विवश होती जा रही हैं। एचडीएफसी,

एलआईसी आवास वित्त, डीएचएफएल और आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) जैसी सभी बड़ी आवास वित्त कम्पनियां लगभग छ: माह पहले के 6.5% की तुलना में इस समय एक वर्षीय जमाराशि के लिए 7% से अधिक की दर प्रदान कर रही हैं। जमाराशियों की ताक में रहने वाले कारपोरेटों को भी ब्याज दरे बढ़ाने पर विवश होना पड़ रहा है।

विदेशी मुद्रा विनिमय

नवम्बर, 2010 माह के लिए लागू विमुअनि (बैंक)/ अनिवि
जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवि जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली (स्वैप दरें)

मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.76219	0.5310	0.7820		

विमुअनि (बैंक) जमाराशियों के लिए लिबोर / अदला-बदली (स्वैप दरें)

मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.76219	0.531	0.782	1.117	1.474
ब्रिटिश पौण्ड	1.48038	1.3220	1.5800	1.8830	2.1630
यूरो	1.50688	1.603	1.811	2.003	2.200
जापानी येन	0.63813	0.392	0.400	0.431	0.486
कनाडाई डालर	1.83500	1.539	1.702	1.891	2.092
आस्ट्रेलियाई डालर	5.58875	5.190	5.270	5.470	5.570

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि

मद	29 अक्तूबर, 2010 के दिन	29 अक्तूबर, 2010 के दिन
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3
कुल आरक्षित निधियां	13,27,098	297,956
क) विदेशी मुद्रा में आस्तियां	11,98,542	269,093
ख) सोना	96,510	21,668
ग) विशेष आहरण अधिकार	23,080	5,182
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधि	8,966	2,013

की स्थिति		

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि 1.63 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ी

आरक्षित निधियों के पुनर्मूल्यन के कारण 8 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि 1.634 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ कर 295.792 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गई। यह निरंतर चौथा सप्ताह था, जिसमें आरक्षित निधियां बढ़ीं। 1 अक्तूबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां 2, 563 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ कर 294.158 बिलियन अमरीकी डालर हो गई थीं।

विनियामकों के कथन

स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक हस्तक्षेप करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि "जरूरत महसूस होने पर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाज़ार में हस्तक्षेप करेगा।" इस वर्ष में भारतीय मुद्रा को पर्याप्त रूप से ऊपर उठाते हुए रिकार्ड विदेशी संस्थागत निवेश के अंतर्वाहों के बावजूद शीर्ष बैंक ने अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया है। गवर्नर का कहना है कि "अंतर्वाहों के ढेलेदार और अस्थिर होने अथवा उनके स्थूल-आर्थिक स्थिति में बाधक होने पर हम हस्तक्षेप करेंगे।"

इसके अलावा गवर्नर इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि हाल के महीनों में जब अधकिांश उभरते बाज़ारों में अंतर्वाहों का तांता लग गया था, तो कतिपय केन्द्रीय बैंकों ने बाज़ारों में हस्तक्षेप किया था। "हालांकि, हमने सितम्बर माह के दौरान किसी अन्य एक महीने की तुलना में रिकार्ड स्तर पर अधिक पोर्टफोलियों निवेश प्राप्त होने के बावजूद यह उपाय नहीं अपनाया। हमारे हस्तक्षेप न करने का कारण यह है कि वृद्धि और निवेश से सम्बन्धित सकारात्मक संभावना की पृष्ठभूमि में हमारे आयात में उछाल आ जाने के कारण चालू खाते के बढ़ते घाटे से प्रेरित हमारी अवशोषण क्षमता भी बढ़ गई है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं ने हस्तक्षेप किया, जिनके पास चालू खाते की अधिशेष राशियां या केवल छोटी अधिशेष राशियां मौजूद हैं। किन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम हस्तक्षेप करेंगे ही नहीं। हमारा हस्तक्षेप चलनिधि की स्थितियों को वास्विक अर्थव्यवस्था में चल रही गतिविधियों से सुसंगत तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए होगा, न कि बदलते आर्थिक मूल तत्वों द्वारा प्रेरित विकासपरक कार्यों को बाधित करने के लिए।"

प्रतिभूत लिखतों के सूचीकरण हेतु सेबी को मासिक सूचना की दरकार

प्रतिभूतिकरण मार्ग के माध्यम से अपने ऋणों को बेचने वाले ऋणदाताओं को अब उनके द्वारा उनके प्रतिभूत लिखतों का सूचीकरण करवाना अपेक्षित होने पर शेयर बाज़ारों को मासिक प्रकटन करना होगा। भारतीय

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने प्रतिभूत लिखतों के लिए निरंतर प्रकटन की अपेक्षाओं वाले एक मानक सूचीकरण करार की घोषणा की है।

पण्य (जिंस) बाज़ार

जिंस बाज़ार का आवर्त सितम्बर में 41% बढ़ा

वायदा बाज़ार आयोग द्वारा यथावर्णित ऊर्जा एवं सराफा, उसके बाद धातु व्यापार और कृषि वस्तुओं द्वारा प्रेरित जिंसों के 23 शेयर बाज़ारों का आवर्त इस वर्ष के सितम्बर माह में 41.13% बढ़ कर 8,95,613 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।

अन्तरराष्ट्रीय समाचार

विदेशी ऋण में 4.1% बढ़ोत्तरी

इस वर्ष की पहली तिमाही में विदेशी ऋण मार्च 2010 के अंत में दर्ज स्तर की तुलना में 4.1% बढ़ गया। जून में समाप्त तिमाही के दौरान उक्त ऋण में 10.8 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोत्तरी हुई तथा वह अल्पावधिक व्यापारिक ऋणों, वाणिज्यिक उधारों और बहु-पक्षीय सरकारी उधारों मे हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण 273.1 बिलियन डालर के स्तर पर पहुंच गया। ऋण में यह वृद्धि तिमाही में अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं तथा भारतीय रुपये के समक्ष अमरीकी डालर में हुई मूल्यवृद्धि के कारण मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर 12.1 मिलियन रही।

3री तिमाही में यू.के. का सकल घरेलू उत्पाद 0.8% बढ़ा; पूर्वानुमान गलत साबित हुए

तीसरी तिमाही में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 0.8% बढ़ी, जो अर्थशास्त्रियों के पूर्वानुमानों की दोगुना थी, क्योंकि सेवाओं और निर्माण ने पुनरुत्थान के संवेग को स्थिर रखने में सहायता की, जिससे अधिकारियों पर प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु पड़ने वाले दबावों में कमी आ गई। पिछली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 1.2% की वृद्धि परिलक्षित हुई थी। ब्लूमबर्ग न्यूज सर्वे में 35 पूर्वानुमानों के औसत के अनुसार अर्थशास्त्रियों ने 0.4% के अभिलाभ का अनुमान लगाया है।

अग्रणी अमरीकी बैंकों में राजस्व में संकुचन

14

गोल्डमैन सैच्स और सिटीग्रुप से हुई शुरूआत के साथ अमरीकी बैंकों में आए राजस्व संकुचन मे मुरझाहट की प्रवृत्ति जारी रह सकती है, क्योंकि उद्योग महान मंदी के बाद उस दौर की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसे उसकी न्यूनतम वृद्धि वाली अवधि कहा जा सकता है। वर्ष 2009 में छ: सबसे बड़े अमरीकी बैंकों द्वारा रिकार्ड राजस्व दर्ज किए जाने के बाद इसके पूर्व वाले एक वर्ष की तीसरी तिमाही में संयोजित निवल राजस्व में औसतन 8% की तथा पिछली दो तिमाहियों की तुलना में 16.3% की कमी आ गई थी।

खाते एवं क्रेडिट कार्ड शुल्कों और उनके साथ ही व्युत्पन्नियों और पूंजी से सम्बन्धित नियमों को प्रतिबंधित करने वाले नये कानून भी उधारदाताओं को निचोड़ रहे हैं।

नयी नियुक्तियां

श्री संजीव बजाज को भारत में क्रेडिट सुइज बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया किया गया है।

श्री ए.के. जगन्नाथन को तमिलनाड मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

पूर्व-प्रदत्त व डेबिट कार्ड अल्प-बैंकिंग सेवा प्राप्त क्षेत्रों का दोहन करेंगे

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ इन्क्लूसिव ग्रोथ सर्विसेज लिमिटेड और इलेक्ट्रा कार्ड सेवाएं बैंक-रहित एवं अल्प बैंकिंग सुविधा प्राप्त खण्डों के लिए एक संकर कार्ड की संयुक्त रूप से शुरूआत कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ कार्ड कहे जाने वाले इस कार्ड में पूर्व-प्रदत्त और डेबिट कार्ड की संयुक्त विशेषताएं निहित हैं। ठीक डेबिट कार्ड की ही भांति कॉमनवेल्थ कार्ड एक बचत बैंक खाते द्वारा समर्थित होता है तथा कार्ड धारक खाते में शेष राशि पर नियमित ब्याज अर्जित करता है।

पीएनबी को वित्तीय सेवा संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति मिली

पंजाब नैशनल बैंक (PNB) को एक वित्तीय सेवा की स्थापना करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इंडिया फैक्टरिंग एण्ड फाइनैंस सॉल्यूशन्स एक ऐसी संयुक्त उद्यम कम्पनी

होगी, जो मूलत: लघु एवं मध्यम उद्यमों और लघु उद्योगों को भिन्न-भिन्न घरेलू फैक्टरिंग उत्पादों के समूह उपलब्ध कराते हुए लेनदारी लेखा क्रय सेवाएं और व्यापार वित्त समाधान प्रदान करेगी।

विजया बैंक यूएई एक्सचेंज ने गंठजोड़ व्यवस्था की

विश्व भर के भारतीयों को सरल मुद्रा अंतरण सुविधा प्रदान करने के लिए विजया बैंक के महा प्रबन्धक श्री एम.बी. गुरुमूर्ति और यूएई एक्सचेंज के कन्ट्री प्रमुख श्री वी. जॉर्ज एन्टोनी ने विजया बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री एस. पणसे की उपस्थिति में आवक मुद्रा अतरण करार का आदान-प्रदान किया।

आईडीबीआई बैंक ने ऊर्जा -बचत उपायों के लिए डब्ल्यूआरआई के साथ समझौता किया

आईडीबीआई बैंक ने अपने उधारकर्ताओं को ऊर्जा की लागत में कमी लाने के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने हेतु अमरीका स्थित पर्यावरणीय शोध संगठन वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (WRI) के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की है। ऊर्जा बचत से सम्बन्धित पहलकदमियों को कार्यान्वित करने की लागत का निधीयन आईडीबीआई बैंक द्वारा किया जाएगा तथा वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट बचत की गारंटी देगा।

इस समझौते के तहत किसी कम्पनी के ऊर्जा बिलों में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान कमी न आने पर और कम्पनी द्वारा ऋण न चुकाए जाने पर आईडीबीआई वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट की गारंटी को लागू कर सकता है। आईडीबीआई बैंक के कार्यपालक निदेशक और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के प्रमुख श्री टी.आर. बजालिया ने बताया कि "ऊर्जा की लागत उत्पादन लागत के 25% जितनी अधिक होती है। लागत में कमी के अलावा उक्त मुहिम का लक्ष्य है पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। यह गंठजोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) खण्ड के लिए है तथा हम इस गंठजोड़ व्यवस्था से गढ़त (forging) इकाइयों, कपड़ा, इस्पात क्षेत्र और होटल उद्योग के लाभान्वित होने की आशा करते हैं।"

विजया बैंक ने मनी-ग्राम के साथ गंठजोड़ व्यवस्था की

विजया बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अल्बर्ट तौरो ने बताया है कि "विजया बैंक और वैश्विक मुद्रा अंतरण कम्पनी मनी-ग्राम इंटरनेशनल ने उनकी गंठजोड़ व्यवस्था की घोषणा की है, जिसमें बैंक अपनी 1, 173 शाखाओं में मनी-ग्राम की तत्काल मुद्रा अंतरण सेवाएं प्रदान करेगा। बैंक के पास एक सुदृढ़ विदेशी मुद्रा विनिमय विभाग है तथा एक लाख से थोड़े ही कम अनिवासी भारतीय खातों के साथ विदेशी मुद्रा

विनिमय कारबार मौजूद है।" उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए कि इनमें से भारी मात्रा में विप्रेषण संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और पश्चिमी देशों से प्राप्त होता है, यह आशा व्यक्त की कि इस गंठजोड़ व्यवस्था से उनकी अनिवासी भारतीय विप्रेषण सेवाओं को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।

एनसीएमएसएल ने इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया

16

नेशनल कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने संपार्श्विक (प्रतिभूति) प्रबन्धन तथा गोदाम सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ गंठजोड़ किया है।

बजाज फाइनैंस, सेन्ट्रल बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों को उधार देने हेतु गंठजोड़ व्यवस्था की

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी बजाज फाइनैंस लिमिटेड (BFL) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया खुदरा एवं लघु एवं मध्यम उद्यम का सह-वित्तीयन करने के लिए गंठजोड़ कर रहे हैं। इस व्यवस्था के एक अंग के रूप में बजाज फाइनैंस लिमिटेड शुल्क के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को प्रत्येक माह में एक नियत अंश प्रदान करते हुए ऋणों का पूर्वेक्षण, हामीदारी तथा शोधन करेगी।

बीमा

'केनरा, एचएसबीसी, ओबीसी लाइफ' ने समूह बीमा में प्रवेश किया

त्रिपक्षीय जीवन बीमा संयुक्त उद्यम 'केनरा, एचएसबीसी, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC) लाइफ इंश्योरेंस' ने समूह बीमा व्यवसाय में अपने प्रवेश की घोषणा की है। उक्त उद्यम ने खुदरा अथवा जीवन बीमा व्यवसाय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रखी है। उक्त बीमाकर्ता अब तीनों भागीदार बैंकों के माध्यम से कारपोरेट खण्ड को लक्ष्यांकित करते हुए ग्राहकों के अपेक्षाकृत बड़े खण्ड के प्राप्त होने की आशा करता है। कारपोरेट कम्पनियों के कर्मचारी लाभों पर संकेन्द्रण के साथ उक्त उद्यम ने एक परंपरागत समूह योजना की शुरूआत की है, जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ यथा- ग्रेच्युटी, अधिवर्षिता / पेंशन, अवकाश नकदीकरण उपलब्ध कराती है।

सूक्ष्मवित्त

शेयर सूक्ष्मवित्त की अस्मिता के साथ विलयन सम्बन्धी वार्ता

हैदराबाद स्थित सूक्ष्म वित्त संस्था शेयर माइक्रोफाइनैन्स लिमिटेड और अस्मिता माइक्रपफाइनैन्स लिमिटेड शेयर के सार्वजनिक निर्गम से पहले संभाव्य विलयन हेतु वार्तालाप कर रही हैं। इस विलयन का लक्ष्य मूल्यांकन को बढ़ावा देना है तथा यह सम्मिलित संस्था (कम्पनी) को सूक्ष्म वित्त संस्था अंतराल में तीसरी सबसे बड़ीं संस्था बना देगा।

17

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को बैंकों से निधियों के प्रवाह में कठिनाई का अनुभव

अपारदर्शी कारपोरेट अभिशासन और कुशीदात्मक ब्याज दरों के सम्बन्ध में हाल ही के विवादों के अनुसरण में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) को एक नये झटके में बैंक उन्हें स्वीकृत ऋण व्यवस्था भी उधार देने से इनकार कर रहे हैं। आसन्न चलनिधि संकट ने कई एक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को बैंकों को ऋण की चुकौती के सम्बन्ध में अधिस्थगन प्राप्त करने हेतु प्रेरित कर दिया है।

एमफिन अथवा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नेटवर्क शीघ्र ही एक बैठक में अधिस्थगन पर विचार-विमर्श करेगा तथा इस मामले को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के नेतृत्व में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के नये सिरे से पुनर्जीवित मंच के पास ले जाएगा, जिसके इस मामले को पुन: भारतीय बैंक संघ (IBA) के पास ले जाने की आशा है।

सिडबी ने बंधन को 350 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) ने बंधन फाइनैन्सियल सर्विसेज को गरीब महिलाओं को पुन: उधार देने के लिए 350 करोड़ रुपये की ऋण व्यवस्था उपलब्ध कराई है। बंधन इस निधि का उपयोग इस वित्त वर्ष में 350 नये उधारकर्ताओं को उधार देने हेतु करेगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने बंधन के प्रस्तावित अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCD) में अभिदान के रूप में 50 करोड़ रूपये की रकम पुन: प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है।

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल के प्रधान मालेगांव होंगे

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं पर भारतीय रिज़र्व बैंक की समिति सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली ऊंची ब्याज दरों, अवपीड़क वसूली प्रक्रिया और बहुविध उधार परंपराओं के मुद्दों की जांच करेगी।

उक्त पैनेल आंध्र प्रदेश में जारी उस अध्यादेश की जांच करेगी, जिसमें सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए राज्य सरकारों के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशक बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य श्री वाई.एच. मालेगांव की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति अपनी रिपोर्ट तीन माह में सौंपेगी। भारतीय रिज़र्व बैंक केवल उन्हीं सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का विनियमन करता है, जो उसके पास गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के रूप में पंजीकृत हैं। जबकि वे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं की एक छोटी संख्या का ही

प्रतिनिधित्व करती हैं, किन्तु सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के कारबार में इनकी हिस्सेदारी 80% है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि उक्त समिति उसकी नीतियों के निहितार्थों और गरीबों एवं अपवर्जितों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का अध्ययन करेगी। यह उनके द्वारा प्रभारित किए जाने वाले ब्याज को यथोचित बनाने के तौर-तरीकों सहित इस क्षेत्र से सम्बद्ध मुद्दों एवं चिंताओं का अध्ययन करेगी। वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सूक्ष्म

उधारदाताओं को ब्याज दरों और अवपीड़क वसूली पद्धतियों को रोकने के सम्बन्ध में एक आचार संहिता अवश्य तैयार कर लेनी चाहिए।

संस्थान समाचार

ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानक

संस्थान "ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानकों" पर एक पाठ्यक्रम की शुरूआत करेगा। उक्त पाठ्यक्रम की शुरूआत भारतीय बैंकिंग आचार एवं मानक बोर्ड (BCSBI) के सहयोग से की जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने 12 नवम्बर, 2010 को अपरान्ह 4.00 बजे "विस्टा", 30वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, केन्द्र-1, कफ परेड, मुंबई-400005 में उक्त पाठ्यक्रम की शुरूआत करने तथा "ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिताएं एवं मानक" शीर्षक वाली पाठ्यसामग्री जारी करने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है। भारतीय बैंकिंग आचार संहिता एवं मानक बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती के.जे. उदेशी इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगी।

अनुपालन पर कार्यशाला

संस्थान ने अनुपालन पर इंटरनेशनल कम्लाएंस एसोसिएशन, लंदन के सहयोग से 20 से 23 अक्तूबर, 2010 के बीच नई दिल्ली और बेंगलूरू में दो कार्यशालाओं, प्रत्येक द्वि- दिवसीय का एक के बाद एक आधार पर आयोजन किया था। सार्वजनिक क्षेत्र / निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के लगभग 40 वरिष्ठ कार्यपालकों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

उच्च अनुपात वाला ऋण

किसी भी प्रकार का ऋण जिसके लिए एक छोटा सा तत्काल भुगतान (down payment) अवश्य किया जाना चाहिए। बंधक के लिए अधिक मूल्य वाले ऋण में आम तौर पर संपत्ति के मूल्य का 80% से अधिक अंश शामिल होता है। अधिकांश अधिक अनुपात वाले गृह ऋणों मे उधारदाता को संरक्षित करने के लिए बीमा सुरक्षा का कोई न कोई रूप आवश्यक होता है। अधिक अनुपात वाले गृह ऋण अपेक्षाकृत कम आय और आस्ति के खरीदारों को अपेक्षाकृत कम हाथ में नकदी से मकान खरीदने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस कारबार की प्रथा की बुद्धिमत्ता पर वर्ष 2008 के बंधक संकट के दौरान प्रश्नचिन्ह लग गया था।

सामान्यतया, उच्च अनुपात वाले ऋणों पर कमतर अनुपात वाले ऋणों की तुलना में अधिक ब्याज वसूल किया जाता है।

शब्दावली

प्रतिभूतिकरण से आशय है वह प्रक्रिया जिसमें किसी इक्विटी पर भावी नकदी प्रवाहों को विपणनयोग्य प्रतिभूतियों में रूपान्तरित करके प्रारंभिक स्तर पर धन प्राप्त हो जाता है। उक्त प्रक्रिया उधारदाताओं को उनकी ऋण आस्तियों को विशेष प्रयोजन संस्था (SPV) को हस्तांतरित करने में समर्थ बनाती है, जो उन निवेशकों को नियमित भुगतान करेगी, जो प्रारंभिक धनराशि लगाते हैं। ऋण की चुकौतियों के अलावा, किसी भी प्रकार की प्राप्य राशियों को प्रतिभूत किया जा सकता है। अतीत में प्रतिभूतिकरण के उदाहरणों में चुंगी वसूली और कलाकारों को रायल्टी के भुगतान शामिल हैं। भारत में अधिकांश प्रतिभूतिकरण सौदे या तो बंधक समर्थित प्रतिभूतियों या फिर आस्ति समर्थित प्रतिभूतियों से सम्बन्धित होते हैं।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत

- पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
  पूर्व-अदायगी के बिना प्रेषित करने का लाइसेंस संख्या एमआर/ तक/ डब्ल्यूपीपी-15 /
  दक्षिण / 2010 - 12 मुंबई

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

77
72
67
62

20

57
52
47
42

01/10/10 04/10/10 05/10/10 08/10/10 12/10/10 14/10/10 18/10/10 19/10/10
20/10/10 21/09/10 26/10/10 27/10/10 28/10/10

अमरीकी डालर यूरो जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
-प्राय: पूरे सितम्बर माह में मुद्रा में मूल्य वृद्धि होती रही।
-अक्तूबर, 2010 के तीसरे सप्ताह के दौरान मुद्रा घट कर 0.6% होगई।
-रुपये में अभिलाभ प्रत्यावर्तित हो गया, क्योंकि कारपोरेटों ने डालर की खरीद बढ़ा दी।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

20800
20600
20400
20200
20000
19800
19600
19400

01/10/10 07/10/10 08/10/10 11/10/10 12/10/10 13/10/10 14/10/10 15/10/10
19/10/10 21/10/10 25/10/10 27/10/10 28/10/10 29/10/10

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

भारित औसत मांग दरें

8.50
8.00
7.50
7.00
6.50
6.00
5.50
5.00

01/10/10 04/10/10 06/10/10 08/10/10 13/10/10 15/09/10 16/10/10 19/10/10
20/10/10 21/10/10 23/10/10 26/10/10 28/10/10 29/10/10

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, अक्तूबर, 2010
मांग दर अधिकांशतया 6 और 7% के बीच मंडराती रही।
चलनिधि की कठिन स्तीति ने माह के अंत में मांग दरों को 8% पर पहुंचा दिया।

श्री आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, श्री आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, 'दि आर्केड', विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड, मुंबई - 400 005 से प्रकाशित।

संपादक : श्री आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
दि आर्केड, विश्व व्यापार केन्द्र, 2री मंजिल, पूर्व स्कंध, कफ परेड,
मुंबई - 400 005
टेलीफोन : 2218 7003 / 04 / 05 फैक्स : 91-22-2218 5147 / 2215 5093
22

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न नवम्बर, 2010